

>

Title: Request for inquiry into the Pradhan Mantri Awas Yojna allocation to beneficiaries in Nandubar Parliamentary Constituency, Maharashtra.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर यहां बोलना चाहूंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री जी के दिशा-निर्देश पर केन्द्र सरकार ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में जो गरीब हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें उनके हक का आवास मिल सके। इसके लिए जो लाभार्थी सूची निश्चित की गई थी, वह बहुत ही पारदर्शिता से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बनाई गई थी।

मेरे नंदूरबार जिले में मुख्य रूप से तीन तालुके- धड़गांव, अक्कलकुआँ और नवापुर हैं, जहाँ पर लाभार्थी सूची के साथ गड़बड़ी की गई है। इसमें दो-तीन तरह से गड़बड़ी की गई है। एक, कई गांवों में लाभार्थियों के नाम बदलकर, कुछ आर्थिक व्यवहार करके दूसरे लोगों के नाम उन लोगों के नाम पर जोड़ दिए गए और दूसरे लोगों को आवास दिया गया जबकि जिन लोगों के नाम उस सूची में थे, उन्हें उनके हक के आवास मिले। कई गांवों में यह भी देखा गया कि जिन लोगों के नाम लाभार्थी सूची में आए थे, उनके नामों के आगे जो बैंक खाते नम्बर दिए गए थे, वे किन्हीं और व्यक्तियों के दिए गए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की किशतें उन बैंक एकाउंट्स पर आने लगीं, तो जिनके नामों से आवास मंजूर हुए थे, उनके खाते में पैसे नहीं आए और किन्हीं अन्य लोगों के एकाउंट्स में पैसे चले गए।

सभापति महोदय, इसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है कि जिनके नाम पर किशतें गई हैं या जिनके नाम पर पैसे गए हैं, उन लोगों ने तो आवास बनाए ही नहीं और उन लोगों ने कागज पर आवास बनाए हैं, ऐसा बताया गया है। जब यह शिकायत दिशा समिति के पास आई, चूंकि नंदूरबार जिले की दिशा समिति की अध्यक्ष मैं खुद हूं, हमारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जो जिला परिषद के सीओ हैं और

डीआरडीआर के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन्हें इस विषय में जाँच करने के आदेश मैंने दिए थे । तीन महीने के बाद दिशा की जब दूसरी मीटिंग हुई, तब यह बात जानकारी में आई कि इस विषय में किसी भी प्रकार की इंकायरी हमारे जिले के अधिकारियों ने नहीं की, बल्कि जिन लोगों ने घोटाला किया है, उन्हें बचाने का काम हमारे जिले के अधिकारी कर रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह का इतना बड़ा घोटाला मेरे नंदूरबार जिले में हुआ है, इसकी सीबीआई जाँच की जाए । मैं यह भी मांग करती हूँ कि जिन गरीब लोगों को आवास मंजूर हुए थे, लेकिन आवास नहीं मिले, उन्हें जल्द-से-जल्द उनका हक दिया जाए, उनका आवास दिया जाए ।